सत्यमेव जयते

संयुक्त प्रगतिशील
गठबंधन सरकार

भारत को प्रगति के पथ पर ले जाते हुए

2004 – 2013

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

"हमारे सामने आर्थिक वृद्धि को साम्यता और सामाजिक न्याय की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की चुनौती मौजूद है। हमारे सामने केवल उपलब्ध संसाधनों के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। एक ओर, ऐसी नीतियों को अपनाना है जो हमारे नागरिकों की रचनात्मकता और आंतरिक उद्यमशीलता को सामने लाती हैं, जो उत्कृष्टता और जोखिम लेने की क्षमता को सम्मानित करती हैं; और दूसरी ओर जिसमें प्रत्येक नागरिक की जरूरतों को पूरा करना, उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने, शिक्षा पाने एवं कल्याण और अवसरों की समानता का अधिकार देने के साथ शांति और सुरक्षा प्रदान करना संभव है।"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

"हमारा काम बहुत सराहनीय और प्रभावशाली रहा है। हमें इसका गर्व है कि हमारी सरकार के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप हमने तीव्र और समावेशी वृद्धि हासिल की है। सामाजिक कल्याण और गरीबी–उन्मूलन के लिए हमने बेजोड़ संसाधन उपलब्ध कराए हैं। बगैर किसी राजनीतिक भेद–भाव के केंद्र ने राज्य सरकारों को बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराया है।"

यूपीए सरकार
हैंडबुक
2004 – 2013

नागरिकों की सुरक्षा
के लिए वचनबद्ध

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के रुझान

स्रोत : गृह मंत्रालय

- यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में तेजी से सुधार आया है और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में एक बहु–उद्देशीय मार्ग अपनाया गया है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग और समन्वय से कार्य करने पर आतंकवादी संबंधी घटनाओं में 10 गुना कमी आई है।
- सरकार जीवन की हानि को सीमित करते हुए विकास तथा रोजगार उत्पादन के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर सकी थी जिससे युवा वर्ग का सशक्तीकरण करने के साथ उन्हें मुख्य धारा में लाया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति

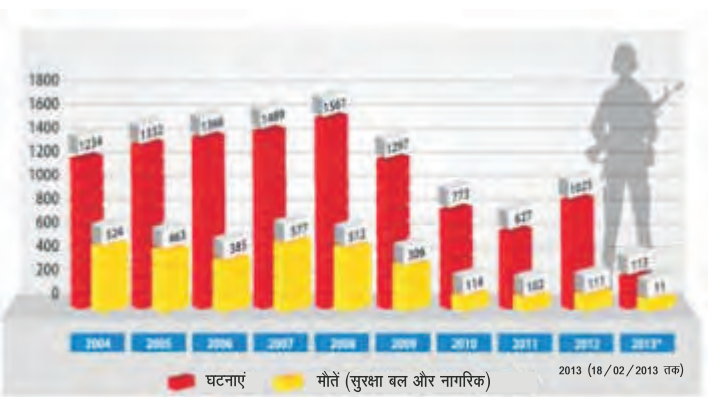

स्रोत : गृह मंत्रालय

- पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा में पर्याप्त सुधार के साथ अतिवाद संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों में तेजी से कमी आई है।
- यूपीए सरकार ने इस क्षेत्र में प्रमुख मूल संरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निधि का निवेश किया है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में से अधिकांश में बेहतर आर्थिक वृद्धि हुई है।
- अधिकांश अतिवादी समूह शांति वार्ता में शामिल हुए थे और इनमें से अनेक ने क्षेत्र की राजनैतिक मुख्य धारा में कदम बढ़ाया है।

वामपंथी अतिवादी हिंसा के रुझान

स्रोत : रक्षा मंत्रालय

- यूपीए सरकार द्वारा सुरक्षा, विकास के क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं उत्तम शासन सुनिश्चित करते हुए समग्र विधि द्वारा वामपंथी अतिवाद को संभाला गया है और इसके नतीजे में वामपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में गिरावट आई है।
- पिछले 4 वर्षों में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं में जीवन की हानि की दर आधी से अधिक घट गई है।
- वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही समेकित कार्य योजना से हिंसा में कमी के साथ विकास की एक नई ऊँचाई पाने में सहायता मिली है।

रक्षा तत्परता
एवं रक्षा कर्मियों के
हितों के लिए समर्पित

रक्षा व्यय

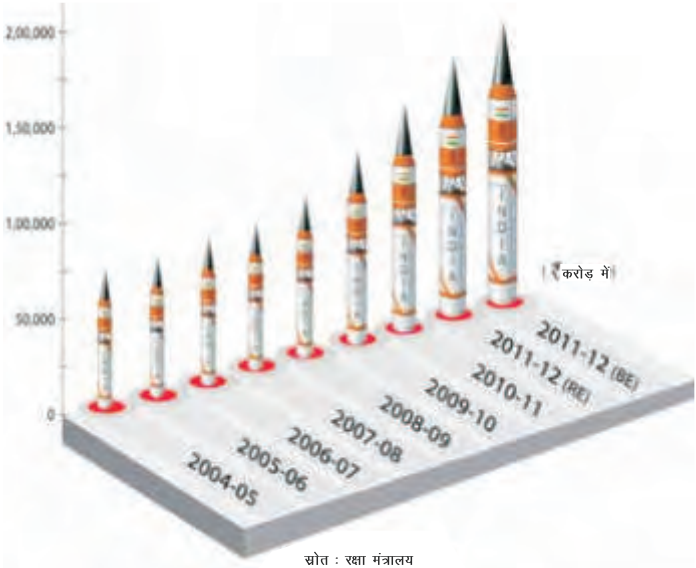

स्रोत : रक्षा मंत्रालय

- यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान रक्षा सेवाओं पर व्यय 154 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।
- देश की रक्षात्मक सुरक्षा के लिए परिष्कृत सैन्य हार्डवेयर, मिसाइल प्रणालियां और निगरानी प्रौद्योगिकी के नये तंत्र शामिल किये गये हैं।
- रक्षा कार्मिकों के कल्याण – सेवारत और सेवानिवृत्त – को बजट आबंटन के दौरान सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है।

लक्ष्मीबेन

महात्मा गांधी नरेगा
की मजबूती के लिए प्रयास

मनरेगा -
जारी किए गए कुल जॉब कार्ड (करोड़ में)

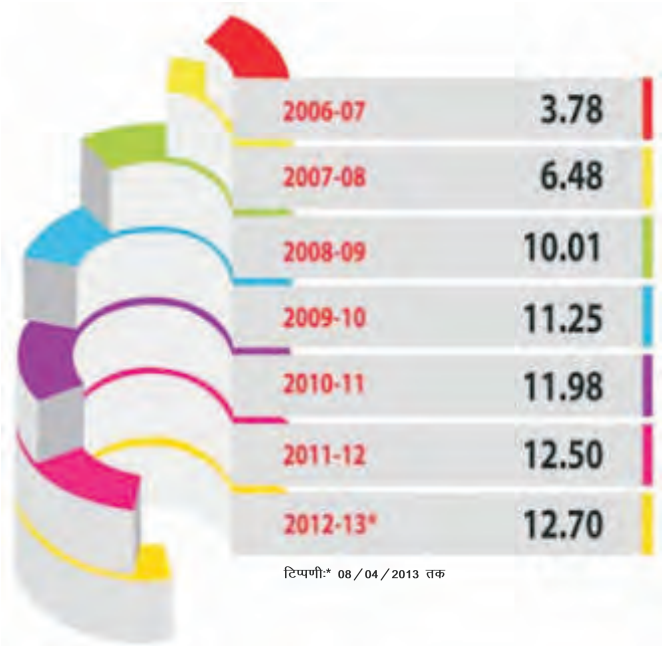

- सबसे बड़े सामाजिक कल्याण की योजना में मनरेगा यूपीए द्वारा 2006 में आरंभ की गई है जो विश्व में अनोखी है।
- भारत के प्रत्येक 5वें ग्रामीण परिवार को इस योजना से लाभ मिलता है जो मुख्यतः गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है।
- योजना आरंभ होने के समय से मनरेगा के तहत प्रति दिन दिया जाने वाला पारिश्रमिक 65 रु. से बढ़कर लगभग 2 गुना अर्थात 128 रु. हो गया है।
- 2012–13 में इस योजना द्वारा 4.8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया, 39,000 करोड़ रु. से अधिक के कुल व्यय पर रोजगार के 213 करोड़ से अधिक श्रम दिवस उत्पन्न हुए।

मनरेगा - प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत पारिश्रमिक

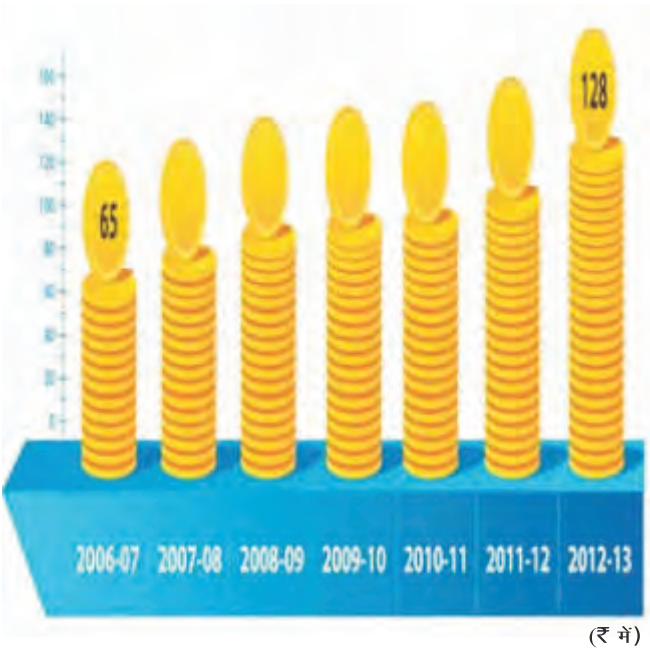

(₹ में)

- मनरेगा ने कृषि श्रमिकों की मोल तोल क्षमता सफलतापूर्वक बढ़ा दी है, परिणाम स्वरूप अधिक कृषि पारिश्रमिक, उन्नत आर्थिक परिणाम और तनाव पूर्ण तरीके से होने वाले प्रवास में कमी।
- अपने आरंभ से इसमें रोजगार पाने वाले घरों की संख्या में, प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत पारिश्रमिक में और कुल उत्पन्न श्रम दिवसों में महिलाओं की प्रतिशत हिस्सेदारी में वृद्धि दर्शाई गई है।
- वर्ष 2006–2007 से 2011–2012 तक कुल बजट परिव्यय 1,72,500 करोड़ रु. रहा।

खाद्य
सुरक्षा सुनिश्चित

खाद्य सब्सिडी के रुझान

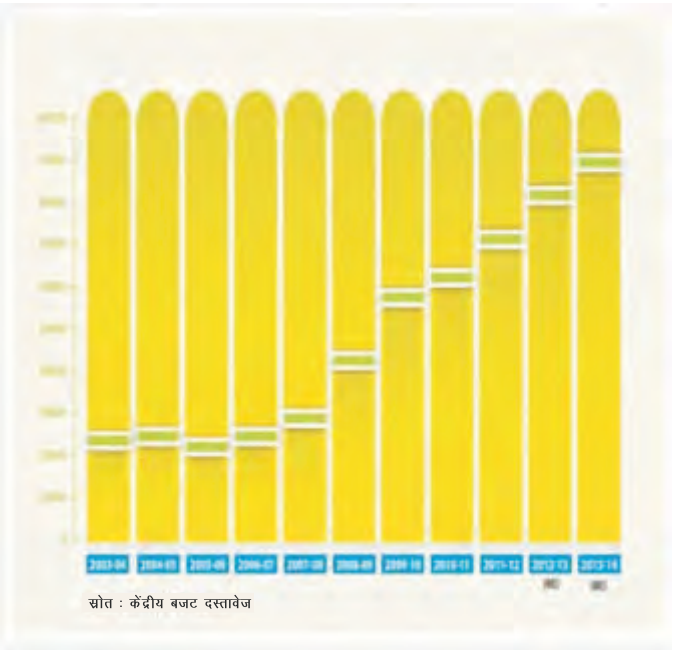

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज

- यूपीए कार्यकाल के दौरान खाद्य सब्सिडी में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। यह सभी के लिए खास तौर पर वंचित वर्गों के लिए वहनीय मूल्यों पर पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की वचनबद्धता दर्शाता है।

- यूपीए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रति वचनबद्ध है, जो अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत ग़रीब परिवारों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति माह तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्य परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज अनुदान राशि पर पाने की पात्रता कानूनी तौर पर देता है।

कुल खाद्यान्न उत्पादन

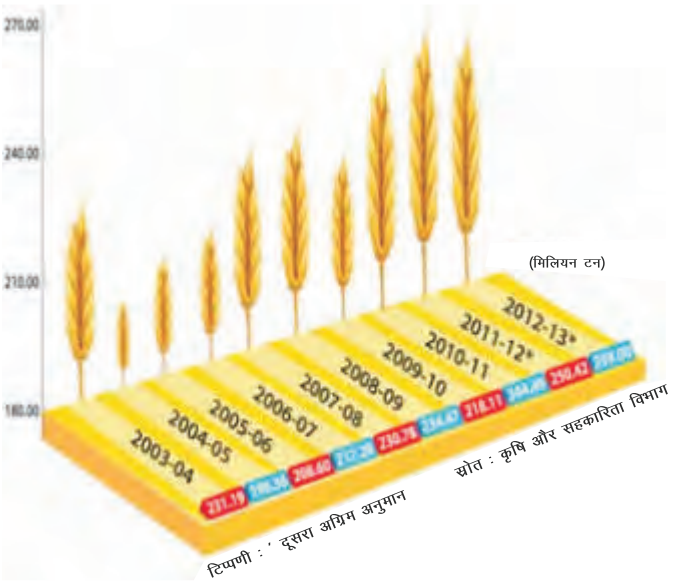

- लोगों में, खास तौर पर वंचित वर्गों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपीए सरकार के संकल्प के साथ गति बनाए रखने के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं।
- कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयासों से हाल के वर्षों में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।
- छोटे किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि ऋण 5 गुना बढ़ गया है।
- खाद्य भंडार साल के दौरान रिकार्ड स्तर पर थे।

स्वास्थ्य
सुरक्षा सुनिश्चित

स्वास्थ्य पर व्यय

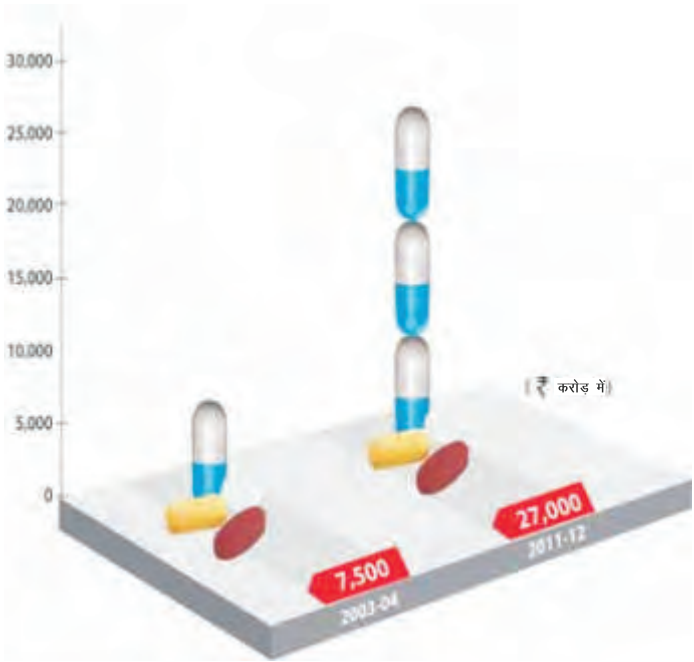

- सार्वजनिक स्वास्थ्य में निरंतर निवेश के बेहतर परिणाम देखे गए हैं और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा स्तरों में तेजी से सुधार आया है।
- ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया गया है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के लिए शहरी निर्धनों को शामिल किया जाएगा।
- पिछले दो वर्षों में स्थानिक पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया है। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई है।

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)
(प्रति 1,000 जीवित जन्म)

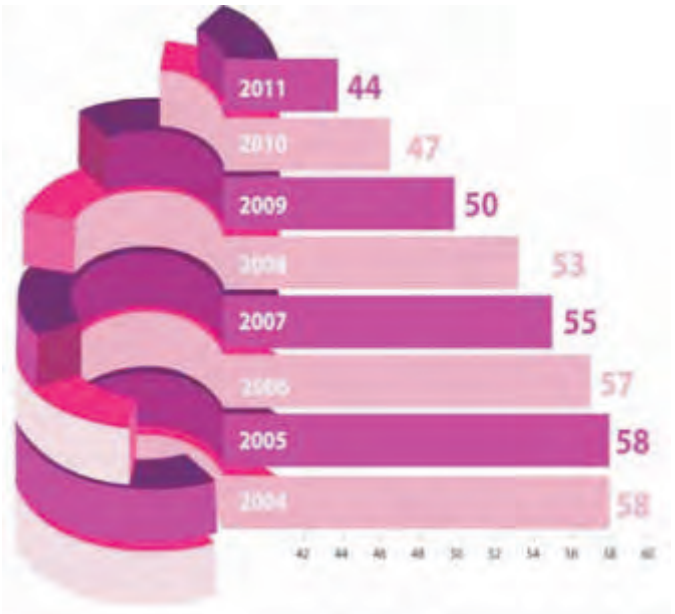

- गर्भावस्था के दौरान और जन्म के समय स्वास्थ्य के उपायों के साथ, 2005 में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 58 से घट कर 2011 में 1000 जीवित जन्म पर 44 हो गई है।
- 2006 से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है अब यह 6.4 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत हो गई है।
- अधिकांशतः उच्चाधिकार कार्य समूह राज्यों में राष्ट्रीय औसत के बराबर या इससे बेहतर गिरावट देखी गई है।

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)

स्रोत : भारत की जनगणना और जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

- यूपीए शासन काल के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों की जीवन प्रत्याशा में 5 वर्ष से अधिक की वृद्धि हुई है और भारतीय लंबा जीवन जी रहे हैं। माताओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों से पिछले 9 वर्षों के दौरान नागरिकों का जीवन बेहतर और लंबा हुआ है।

- 11वीं योजना से 3 लाख करोड़ रु. की राशि का स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन 12वीं योजना में बढ़ा कर 90 हजार करोड़ रु. किया गया है जिसमें 335 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

- बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए समेकित बाल विकास योजना के आवंटन 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 गुना बढ़ गए हैं।

HEALTH
FITNESS

समाज में
विशेष वर्गों के लिए
सामाजिक सुरक्षा

अल्पसंख्यकों पर वास्तविक व्यय
(31 दिसंबर तक)
केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

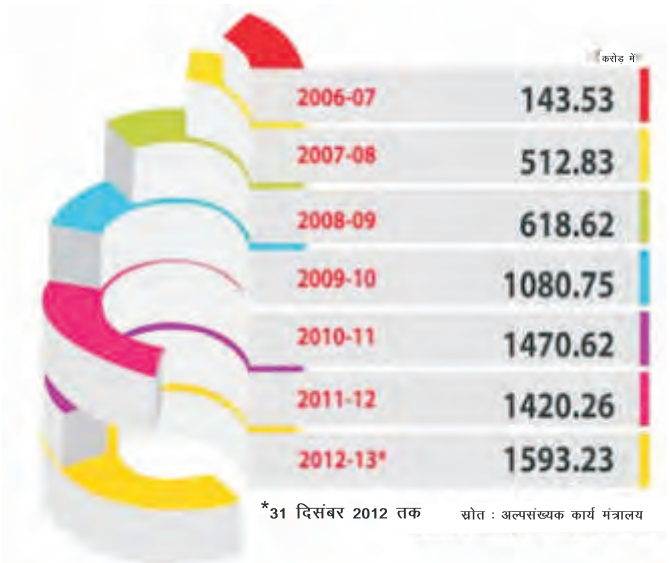

- यूपीए सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 2004–05 के बाद से अल्पसंख्यकों पर होने वाले व्यय में दस गुना वृद्धि हुई है।

- अल्पसंख्यकों की प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष सहायता के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हैं।

- बैंकों से सभी प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का पंद्रह प्रतिशत अब अल्पसंख्यकों तक पहुंचता है और उन्हें छोटे व्यवसायों को शुरू करने और इसमें विस्तार के लिए मदद पहुंचाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय निधि

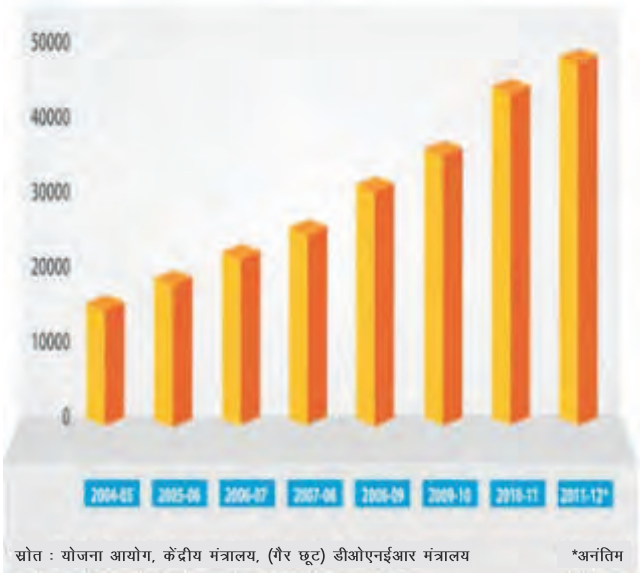

स्रोत : योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रालय, (गैर छूट) डीओएनईआर मंत्रालय *अनंतिम

- पूर्वोत्तर क्षेत्र की वृद्धि दर अब केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- अब यह अधिदेश है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने योजना बजट का 10 प्रतिशत आवंटित करेंगे।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष करों सहित विशेष कर रियायतें दी जा रही है।

B.U.G.H.S.
CLASS
SUB
PER
DATE
TOPIC

बेहतर शिक्षा

उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या

स्रोत : उच्च शिक्षा विभाग

- 2004 से 2013 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 17 से बढ़कर 44 हुई है।
- इस अवधि के दौरान 7 मौजूदा आईआईटी में 9 नई आईआईटी जोड़ी गई थीं।
- इस अवधि में आईआईएम की संख्या दो गुना से अधिक बढ़कर 6 से 13 हो गई। इस अवधि में पांच आईआईएसईआर और 2 आईआईआईटी जोड़े गए थे।

शिक्षा के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय

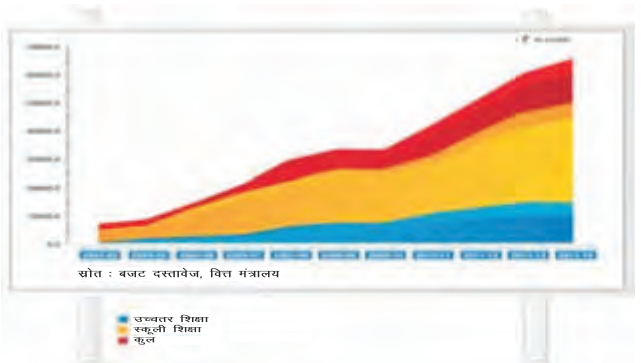

स्रोत : बजट दस्तावेज, वित्त मंत्रालय

- यूपीए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिए परिव्यय में लगातार वृद्धि की है जिससे स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा लेने वाले छात्रों में वृद्धि हुई है।
- बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने के लिए यूपीए सरकार ने उच्चतर शिक्षा में अभूतपूर्व निवेश किया है।
- एक नई योजना – आरयूएसए (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) बनाई गई है ताकि उच्चतर शिक्षा स्तर तक ज़्यादा छात्र पहुंच सकें और उनको हुनरमंद किया जा सके।

स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात

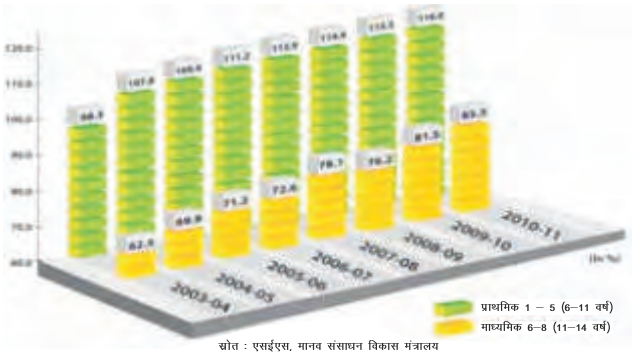

स्रोत : एसईएस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- यूपीए सरकार द्वारा लाए गए शिक्षा का अधिकार कानून से पूरे देश के स्कूलों में नामांकन में व्यापक सुधार आया है।
- देश में प्राथमिक स्कूल स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को काफी हद तक हासिल किया है।
- स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर कम होने से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों की संख्या बढ़ी है।

मध्याह्न भोजन योजना पर व्यय

- 10 करोड़ से अधिक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत वे प्रति दिन पौष्टिक गर्म भोजन प्राप्त करते हैं।
- इस योजना से देश भर के प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति में सुधार लाने में सहायता मिली है।
- 2004 से अब तक यूपीए शासन के दौरान मध्याह्न भोजन के लिए आवंटन में छह गुना वृद्धि की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय

- भारत में साक्षरता के बेहतर स्तर के लिए सर्व शिक्षा अभियान के व्यय में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या

- एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूपीए सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को लागू किया, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की शिक्षा का सार्वभौमीकरण हुआ।

- अधिनियम लागू होने के समय से 30,888 प्राथमिक स्कूल भवन, 10,644 उच्च प्राथमिक स्कूल भवन, 6,88,385 अतिरिक्त कक्षा कक्ष 5,18,700 शौचालय सुविधाएं बनाई गई तथा 7,00,475 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा में नामांकन

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईएनसी

- उच्च शिक्षा संस्थानों में सामान्य नामांकन अनुपात पिछले 10 वर्षों के दौरान 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

- इंजीनियरी, मेडिकल और अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

- एमईटीए विश्वविद्यालयों और पाठ्यक्रम के लचीलेपन जैसे उपायों के साथ, देश 20 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करने के लिए तैयार है जो अंतर्राष्ट्रीय औसत है।

किसान कल्याण

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

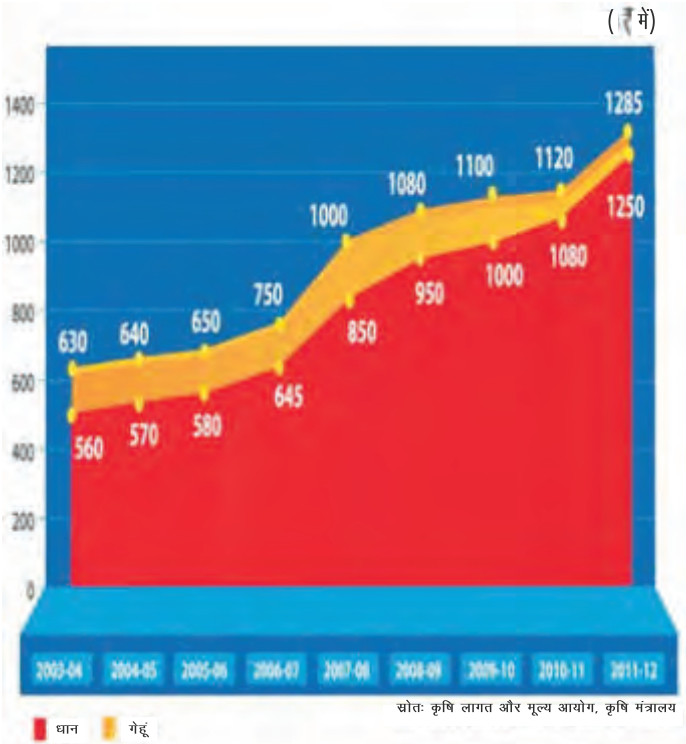

स्रोतः कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय

- किसान का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यूपीए सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाती रही है।
- गेहूं और धान दोनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004–05 से 2012–13 तक दो गुने से अधिक हो गया है।
- मोटे अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन गुना बढ़ गया है और अब इस अनाज का उत्पादन करने वाले उपेक्षित किसानों को मिलने वाला समर्थन गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से बेहतर है।

वर्षा सिंचित क्षेत्र समर्थन
(केंद्र द्वारा कार्यक्रम के तहत जारी)

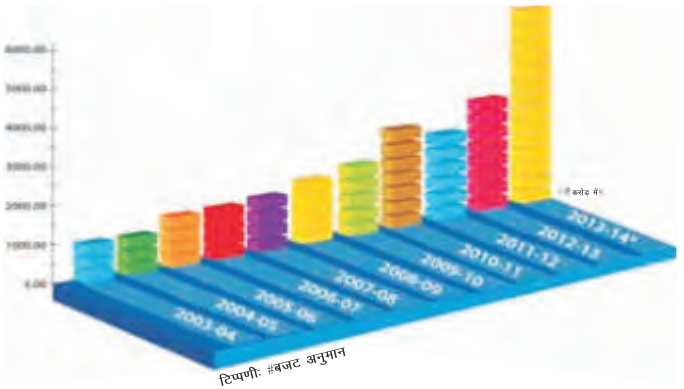

- वर्षा सिंचित क्षेत्र समर्थन यूपीए सरकार के कार्यकाल में 5 गुना बढ़ गया है जिससे उपेक्षित किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता दी जाती है।
- इस प्रयास से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के किसानों को मुख्य रूप से सहायता दी गई है, जहां मानसून की कमी है।
- इस उपाय से सूखे के दौरान भी किसानों को सहायता दी गई है।

कृषि क्रेडिट

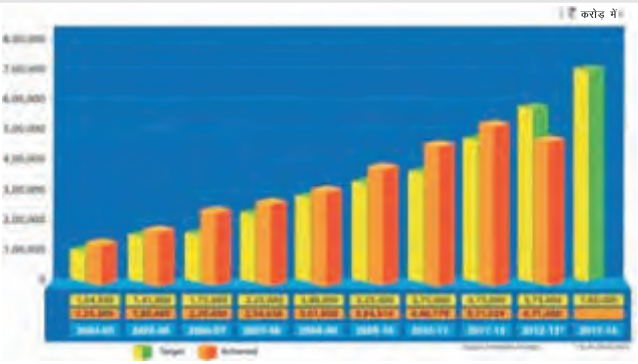

- यूपीए सरकारों के दौरान कृषि क्रेडिट आवंटन में 700 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा 650 लाख से अधिक किसानों को वित्तीय मदद दी गई है।
- कृषि गतिविधि में किसानों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

आईटी और
टेलीकॉम सेक्टर

ग्रामीण दूरघनत्व

स्रोत : दूरसंचार विभाग (प्रतिशत में)

- यूपीए सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन की संख्या 25 गुना बढ़ गई है।
- भारत में दुनिया के सबसे कम दूरसंचार मूल्य होने के कारण यह गरीबों के बीच भी पहुंच सका है।
- जो व्यक्ति निजी फोन नहीं रख सकते उन्हें ग्राम स्तरीय टेलीफोनी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।
- ब्रॉडबैंड की पहुंच 2014 तक 2.5 लाख गांवों तक होगी।

इंटरनेट और ब्रॉडबैण्ड सेवा

(कनेक्शन मिलियन में)

स्रोत : ट्राई

- यूपीए कार्यकाल के दौरान इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत उच्च शिक्षा के 998 संस्थानों को हाई स्पीड डेटा लिंक से जोड़ा गया है।
- ब्रॉडबैण्ड सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश में 32 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए हैं, जिससे लोगों को 121 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है।

आर्थिक
सुरक्षा

स्थिर (2004-05) मूल्य पर मासिक प्रति व्यक्ति खपत

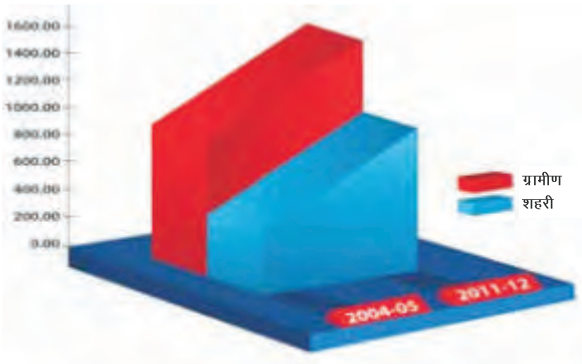

- भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में असाधारण वृद्धि हुई है और लोगों को आर्थिक विकास के फल मिले हैं।
- यूपीए सरकार की निर्धन उन्मुख नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 1999 से 2004 के दौरान केवल 0.8 प्रतिशत थी।
- इससे यह तथ्य सिद्ध हुआ है कि यूपीए के दौरान आर्थिक वृद्धि समावेशी और व्यापक दोनों है।

औसत सकल घरेलू उत्पाद दर

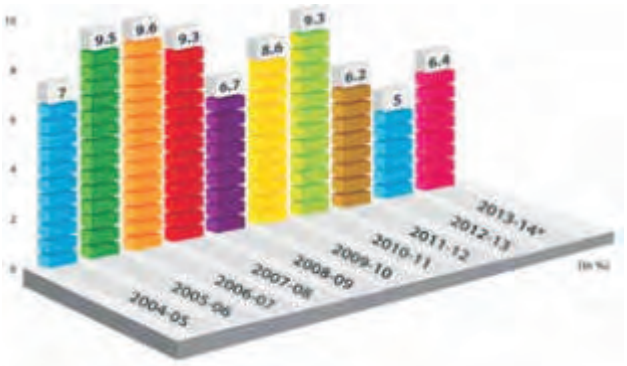

- यूपीए सरकार के दौरान (2004–05 से 2013–14) औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इस अवधि के दौरान दो वैश्विक मंदियों के बावजूद 7.7 प्रतिशत रही है।
- कृषि वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। यह 10वीं और 11वीं योजना के दौरान क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत थीं। इसमें 12वीं योजना के दौरान 4 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।
- वर्तमान मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 9 वर्षों के दौरान लगभग 3 गुना बढ़ गया है।

प्रति व्यक्ति आय
(वर्तमान मूल्य में)

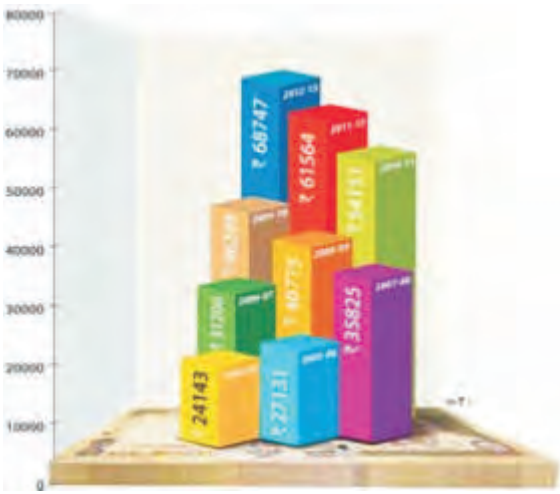

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण

- भारत में प्रति व्यक्ति आय यूपीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद से लगभग 3 गुना बढ़ गई है।
- समावेशी विकास की नीतियों के परिणामस्वरूप कृषि में वास्तविक पारिश्रामिक पूर्व 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 1.1 प्रतिशत की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान 6.8 प्रतिशत बढ़ा है।
- प्रति व्यक्ति आय पिछले 9 वर्षों के दौरान लगभग 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष औसत पर बढ़ी है।

लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों में क्रेडिट का प्रवाह
(बकाया राशि)

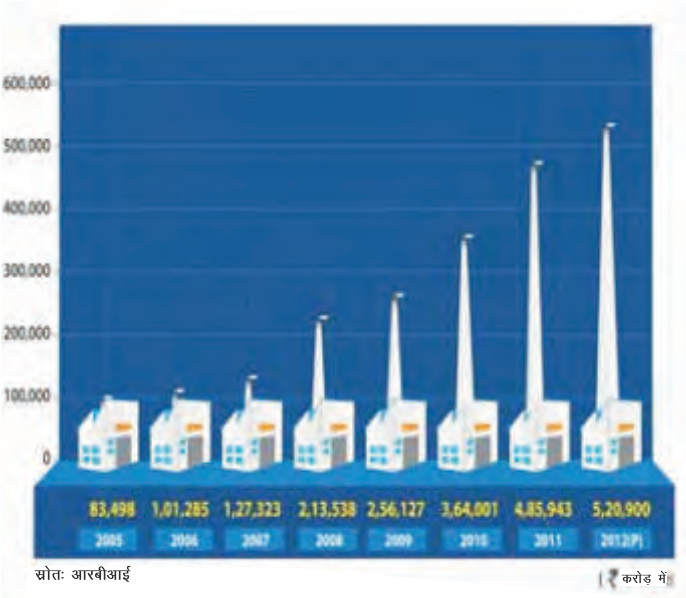

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्रेडिट और ऋण की सुविधाएं पिछले 5 वर्षों के दौरान दो गुने से अधिक हो गई हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एसएमई के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक अलग स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति दी है।
- पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम द्वारा 6.74 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर देकर 80 हजार सूक्ष्म उद्यमों को भी समर्थन दिया गया है।

शहरी कल्याण
एवं
आधारभूत संरचना

रेलवे
(वार्षिक वृद्धि)

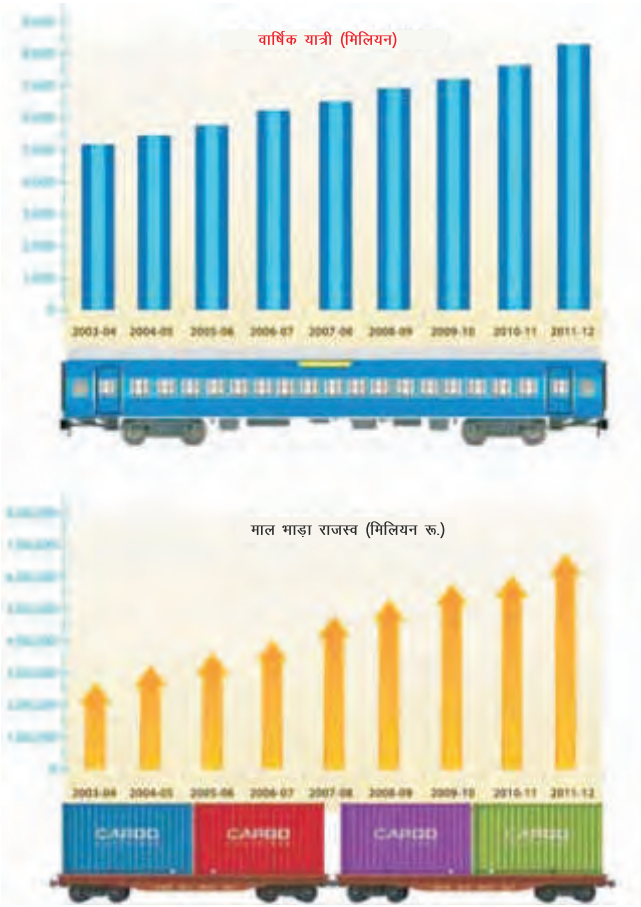

- भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क तंत्रों में से एक है जिसमें प्रति वर्ष 850 करोड़ व्यक्ति यात्रा करते हैं।
- यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेल द्वारा ढोए गए माल की मात्रा दो गुनी होकर एक वर्ष में 1 बिलियन टन से अधिक पहुंच गई है।
- वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर पर कार्य आरंभ हो गया है जो रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाएगा और उन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

सड़कों की लंबाई (वार्षिक वृद्धि)

- दो लाख किलोमीटर से अधिक नई सड़कें ग्रामीण सड़क नेटवर्क में जोड़ी गई हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों के जुड़ाव में और भी अधिक सुधार लाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले 9 वर्षों में 17,394 कि.मी. सड़कों का निर्माण पूरा किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर व्यय

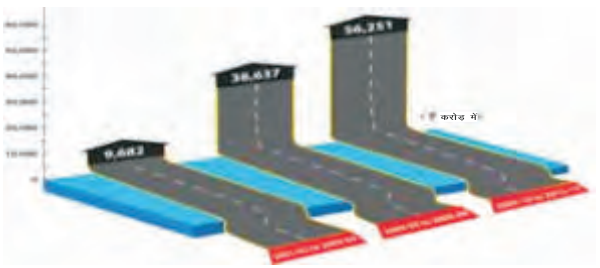

- यूपीए सरकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर निवेश कई गुना अधिक हुआ है।
- सभी मौसमों में इस्तेमाल योग्य 20,100 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण/उन्नयन किया गया है और इस पर 6,450 करोड़ का व्यय किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ाव से छोटे किसानों को अपने कृषि माल बाजार तक लाने में सहायता मिली है जहां वे अपने उत्पादों के लिए बेहतर लाभ पाते हैं।

युवा
कल्याण

बेरोजगारी की दर

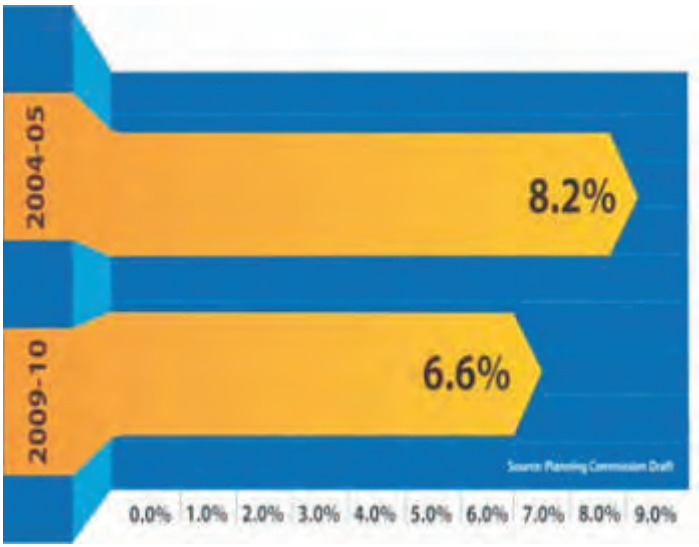

- देश में यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी की दर में लगातार कमी आई है।
- 2004–05 से 2011–12 तक औसत औद्योगिक वृद्धि 8.5 प्रतिशत से अधिक रही है, जो पहले कभी नहीं रही और जिससे युवा लोगों के लिए उत्पादक रोजगार उत्पन्न हुए हैं।
- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र की सहायता से 5 करोड़ लोगों के कार्यबल को अगले 5 वर्षों में प्रशिक्षित किया जाना है।

क्षेत्रीय विकास

निर्धनता अनुमान
(तेंदुलकर विधि)

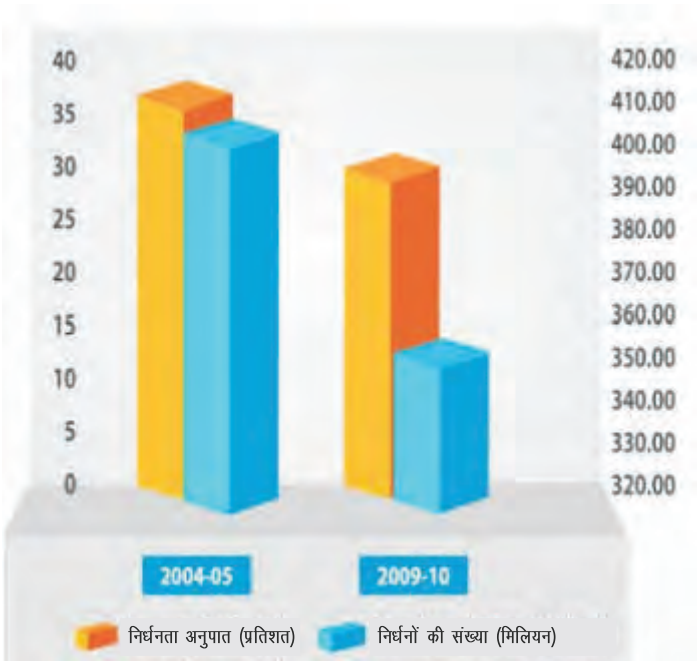

- यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत में गरीबी की दर में जो कमी आई है इतनी कमी पहले कभी नहीं देखी गई।
- 2004–12 के दौरान निर्धनता में औसत कमी पिछले दशकों की दर से लगभग 2 गुना रही है।
- सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 16 फ्लैगशिप कार्यक्रम आरंभ किए और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनके आवंटन दो गुने से अधिक किए गए हैं।

प्रमुख योजनाओं के निर्धारण की रूपरेखा

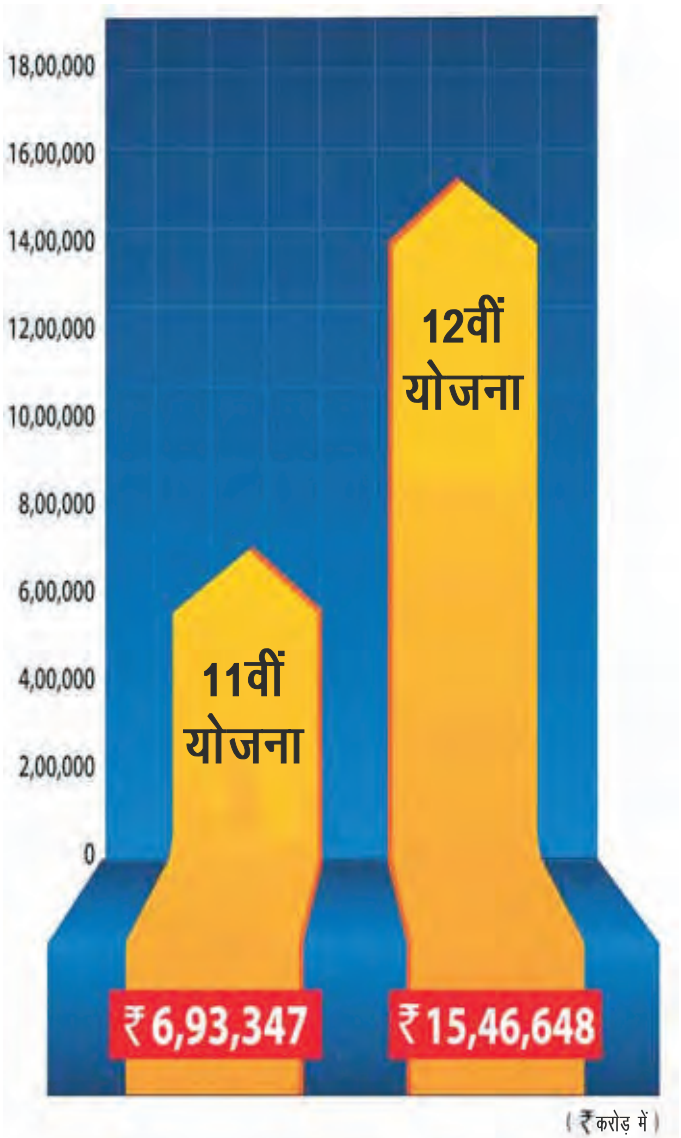

*विवरण अंतिम पृष्ठ पर

ऊर्जा
सुरक्षा

विद्युत क्षेत्र - उत्पादन और क्षमता में वृद्धि

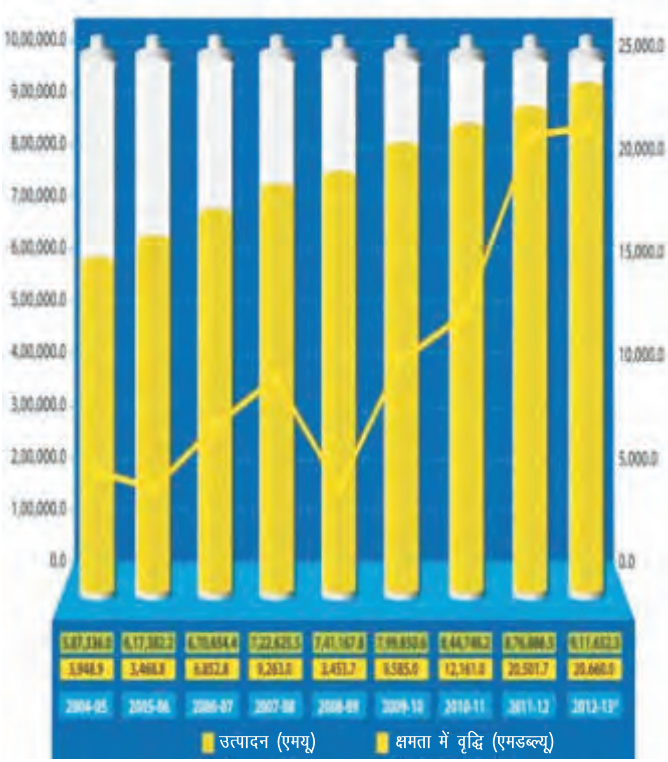

- भारत ने पिछले 9 वर्षों में विद्युत उत्पादन में बहुत अधिक क्षमता वृद्धि की है जो स्वतंत्रता के समय की पूरी अवधि से अधिक है।
- 2002 में 559 किलोवॉट घंटा की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2011 में बढ़कर 813 किलोवॉट घंटा हो गई।
- अक्षय संसाधनों और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

पर्यटन
पर ज़ोर

भारत में पर्यटन

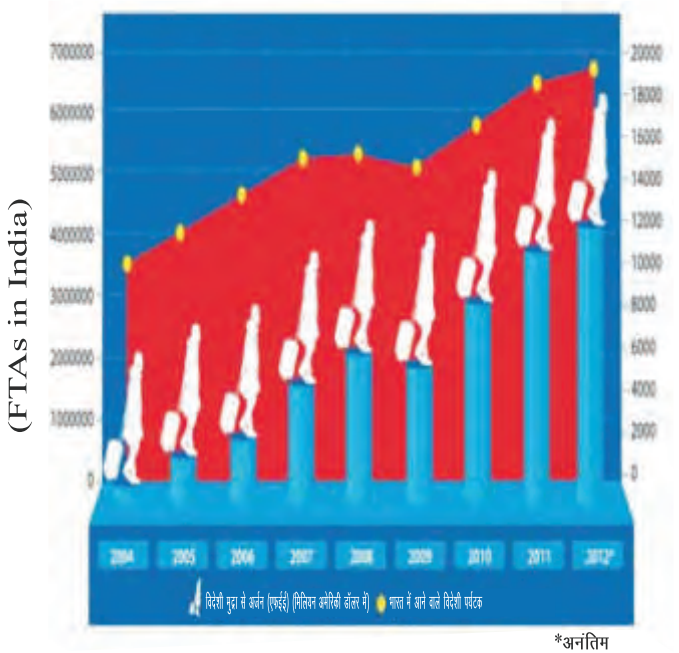

- भारत यूपीए कार्यकाल के दौरान दुनिया भर के पर्यटकों का मनपसंद गंतव्य बन गया है जिसका श्रेय 'अतुल्य भारत' अभियान को जाता है।
- आने वाले पर्यटकों की संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पिछले 9 वर्षों में पर्यटन से विदेशी मुद्रा राजस्व दो गुना हो गया है।
- जम्मू और कश्मीर राज्य में भी इस अवधि के दौरान असाधारण वृद्धि देखी गई है, क्योंकि लोग मनोरंजन और धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में यहां आए हैं।

16 फ्लैगशिप योजनाएं – 11वीं और 12 वीं योजना (करोड़ रु.)

सं.	फ्लैगशिप योजनाएं	11वीं योजना	12वीं योजना	प्रतिशत वृद्धि
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	143,042	165,500	15.70
2.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	41,823	63,585	52.03
3.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	77,576	192,726	148.44
4.	मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	38,490	90,155	134.23
5.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	65,790	124,013	88.05
6.	राजीव गांधी पेयजल और स्वच्छता मिशन (आरजीडीडब्ल्यूएसएम)	44,670	107,015	139.57
7.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	24,161	48,642	101.32
8.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	66,127	250,000	278.06
9.	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	35,334	76,678	117.01
10.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	34,795	101,917	192.91
11.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	22,165	63,246	185.34
12.	समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)	21,882	108,503	395.86
13.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	38,824	91,435	135.51
14.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएमएल)	11,320	29,006	156.24
15.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	21,651	23,397	8.07
16.	त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)	5,697	10,830	90.10
	महा योग	693,347	1,546,648	123.07

मूद्रकः पारस ऑफसेट प्रा॰ लि॰